

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 757] No. 757] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 985(अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उप-धारा (1), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू नहीं होगी, जहां तक इसका संबंध भारतीय रिजर्व बैंक के 26 फरवरी, 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.98/21.04.132/2013-14 के द्वारा दी गई अनुमित के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत किसी प्रतिभूति कंपनी या पुनर्संरचना कंपनी को 26 फरवरी, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक बेची गई अनर्जक आस्तियों (जहां विक्रय प्रतिफल निवल अंकित मूल्य से कम हो) के विक्रय से हुई किसी कमी के कारण दो वर्ष से अधिक की ऋण परिशोधन अवधि का है।

[फा. सं. 16/5/2013-बीओ-II(**भाग**)]

डॉ. शशांक सक्सेना. आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 985(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the

1644 GI/2015 (1)

Reserve Bank of India, hereby declares that sub-section (1) of section 15 of the Banking Regulation Act, 1949 shall not apply to scheduled commercial banks in so far as the amortisation over a period of two years of any shortfall arising out of sale of non-performing assets effected from 26th February, 2014 to the 31 March, 2015 (where the sale consideration is lower than the net book value) to any Securitisation Company or Reconstruction Company, registered under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, as permitted by the Reserve Bank of India vide its circular number DBOD.BP.BC.No.98/21.04.132/2013-14, dated the 26th February, 2014, is concerned.

[F. No. 16/5/2013-BO.II(Part)]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Advisor